



The Prisons (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2002

Act 16 of 2002

Keyword(s):

Remuneration of Prisoners, Criminal Prisoner, Offence, Prison

Amendment appended: 30 of 2021

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

No. 1767(2)/XVII-V-1-1(KA)30-2002

Dated Lucknow, September 17, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Karagar (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhnyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhnyam Sankhya 16 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 2002:-

THE PRISONS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2002

(U. P. ACT NO. 16 OF 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Prisons Act, 1894 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Prisons (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2002.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of new section 36-A in Act no. IX of 1894

2. *After section 36 of the Prisons Act, 1894, the following section shall be inserted, namely:-*

“36-A(1) Every convicted criminal prisoner employed for labour in a ^{Remuneration of Prisoners} prison and working satisfactorily shall be entitled to get such remuneration as may be prescribed by the State Government:

Provided that out of the amount payable to a convicted criminal prisoner under this sub-section, an amount not exceeding 20 per cent thereof shall be deducted and be paid as compensation to the deserving victims of the offence committed by that prisoner.

(2) All deductions made under sub-section (1) shall be credited to a common fund to be created for the purpose.

(3) The creation of the fund, credit of amount therein and the operation thereof shall be regulated in such manner as may be prescribed.”

By order,
R. B. RAO,
Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble Supreme Court has in its decision dated 24.09.98 in Criminal Appeal No. 308 of 1986 State of Gujrat & Others Vs Gujrat High Court directed that the prisoners who are employed for labour shall be paid remuneration therefor and a portion of such remuneration be paid to the deserving victims of the offence committed by such prisoners and recommended that the State Government may make law in this regard. Accordingly it has been decided to amend the Prisons Act, 1894 (Act no. IX of 1894) in its application to Uttar Pradesh to provide for,-

(a) payment of remuneration to all convicted criminal prisoners employed for labour in a prison :

(b) deduction of a portion of remuneration not exceeding twenty per cent and its payment to the deserving victims as compensation :

(c) creation of a common fund for credit of amount be deducted and its operation.

The Prisons (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2002 is introduced accordingly.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 अगस्त, 2021

भाद्रपद 3, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 819/79-वि-1-21-1(क) 34-2020

लखनऊ, 25 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर दिनांक 9 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कारागार अधिनियम, 1894 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या
9 सन् 1894 की
धारा 3 का
संशोधन

2-कारागार अधिनियम, 1894 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में -

(क) खण्ड (1) में, उप खण्ड (ख) में शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1882) की धारा 541" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 417" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (3) में शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1882)" अथवा "बन्दी अधिनियम, 1871 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1871) के अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) या बन्दी अधिनियम, 1900 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1900) के अधीन" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (7) में शब्द "उप महानिरीक्षक, कारागार में ऐसा उप महानिरीक्षक सम्मिलित है," के स्थान पर शब्द "अपर महानिरीक्षक, कारागार, और उप महानिरीक्षक, कारागार में, ऐसे अपर महानिरीक्षक कारागार और उप महानिरीक्षक, कारागार सम्मिलित हैं" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (2) में शब्द "उप महानिरीक्षक, कारागार" के स्थान पर शब्द "अपर महानिरीक्षक कारागार और उप महानिरीक्षक, कारागार" रख दिये जायेंगे।

नई धाराओं 42क
एवं 42ख का
बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"42क-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के बन्दी द्वारा कतिपय प्रतिकूल होते हुये भी किसी बन्दी द्वारा बेतार संचार युक्ति अथवा किसी युक्ति धारित किया जाना या उसे प्रचालित किया जाना प्रतिरूपधारक के प्रवेश का प्रतिषेध और किसी "प्रतिरूपधारक" का कारागार में प्रवेश प्रतिषिद्ध होगा।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनार्थ,-

(क) शब्द "बेतार संचार युक्ति" में मोबाइल फोन, वाई-फाई, ब्लूटूथ, निकट क्षेत्र संचार (एन0एफ0सी0), टैबलेट, वैयक्तिक कम्प्यूटर, कम्प्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, जिनका प्रयोग शाब्दिक, अशाब्दिक जैसे संचार हेतु किया जाय, इण्टरनेट, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जी0पी0आर0एस0), ई-मेल, शार्ट मैसेज सर्विस (एस0एम0एस0), मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस (एम0एम0एस0) या अन्य कोई उपस्कर यथा मोबाइल सिम (अधिदाता पहचान मोड्यूल, या चिप आदि) जिन्हें किसी समान प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा सके, सम्मिलित होंगे।

(ख) शब्द "प्रतिरूपधारक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी कारागार के परिसर में फोटो, नाम, पता या किसी अन्य पहचान विवरणों के साथ प्रवेश करता है और जिसके सत्यापन पर समस्त अथवा इनमें से कोई एक विवरण गलत पाये जाते हैं/पाया जाता है।

42ख-जो कोई धारा 42-क के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह धारा 42 क के दोषसिद्ध होने पर ऐसे कारावास, जो तीन वर्ष तक होगा और ऐसे जुर्माने, जो पच्चीस हजार रुपये तक होगा या दोनों से दण्डित किये जाने का भागी होगा।

परन्तु यह कि यदि कोई बन्दी किसी कारागार परिसर के अन्दर अथवा उसके बाहर कोई अपराध करने का प्रयास करने, दुष्प्रेरित करने, षडयन्त्र करने अथवा कारित करने के लिये किसी बेतार संचार युक्ति का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तथा जिसके परिणामस्वरूप कोई अपराध कारित किया जाता है तो दोषसिद्ध होने पर उसे ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और पाँच वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने, जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।"

5-मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :- धारा 43 का संशोधन

"43-धारा 42-ख के अधीन अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय संज्ञेय और अजमानतीय अपराध होना;

धारा 42-ख के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।"

उद्देश्य और कारण

कारागार अधिनियम, 1894, कैदियों की सुरक्षित एवं निरापद अभिरक्षा, उनके भरण-पोषण, उनकी प्रविष्टि एवं अवमुक्ति, स्वास्थ्य, श्रम, जेल अनुशासन को अनुरक्षित रखने हेतु जेल अपराधों के लिए दण्ड और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के कर्तव्यों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है। कैदियों द्वारा मोबाइल फोन और बेतार युक्तियों का उपयोग किये जाने और प्रतिरूपण द्वारा व्यक्तियों के प्रविष्ट होने के दृष्टांत प्रायः परिलक्षित होते हैं। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम में संशोधन करके कारागार में मोबाइल फोन या अन्य बेतार युक्तियाँ धारित करने या उनका उपयोग करने हेतु कठोर उपबन्ध किये जायं और मिथ्या पहचान के आधार पर प्रतिरूपक के कारागार में प्रविष्ट होने के लिये पर्याप्त दण्ड का उपबन्ध किया जाय।

तदनुसार कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 819(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-34-2020

Dated Lucknow, August 25, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Karagaar (Uttar

Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 9, 2021:

THE PRISONS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 30 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

furth^r to amend the Prisons Act, 1894, in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy First Year of the Republic of India as follows :-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Prisons (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2020.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 3 of Act no. 9 of 1894

2. In section 3 of the Prisons Act, 1894 hereinafter referred to as the principal Act -

(a) in clause (1), in sub-clause (b) for the words and figures "section 541 of the Code of Criminal Procedure 1882 (10 of 1882)" the words and figures "section 417 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act no. 2 of 1974)" shall be substituted;

(b) in clause (3) for the words and figures "the Code of Criminal Procedure 1882 (10 of 1882)" or "under the Prisoners Act 1871 (5 of 1871)" the words and figures "the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) or under the Prisoners Act, 1900 (Act no. 3 of 1900)" shall be substituted;

(c) in clause (7) for the words "to Deputy Inspector General of Prisons, includes such Deputy Inspector General" the words "to the Additional Inspector General of Prisons and the Deputy Inspector General of Prisons, includes such Additional Inspector General of Prisons and Deputy Inspector General of Prisons" shall be substituted;

Amendment of section 5

3. In section 5 of the Principal Act in sub-section (2) for the words "Deputy Inspector General of Prisons" the words "to the Additional Inspector General of Prisons and the Deputy Inspector General of Prisons" shall be substituted;

Insertion of new sections 42A and 42B

4. After section 42 of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely :-

"42A. Notwithstanding anything to the contrary in any other provision of this Act, the possession or operation of a wireless communication device by any prisoner and the entering of an impersonator in a prison shall be prohibited.

Prohibition of certain device by prisoner or entering of an impersonator as for

Explanation :- for the purpose of this section, -

(a) the words "wireless communication device" shall include mobile phone, wi-fi, Bluetooth, near field communication (NFC), tablet, personal computer, computer, laptop, palmtop used for the communications like verbal, non-verbal, internet, general packet radio service (GPRS), e-mail, short message service (SMS), multimedia message service (MMS) or any such equipment such as mobile sim (Subscriber Identification Module or Chip etc.) which may be used for any similar purpose.

(b) The word "impersonator" means a person who enters premises of a prison with a photo, name, address or any other identity particulars and on verification of whose all or any one of such particulars are found to be false.

"42B. Whoever contravene the provisions of section 42A shall on
Punishment for Contravenes be liable to be punished with imprisonment which
contravention of shall extend up to three years and with fine which shall extend
section 42A up to twenty five thousand rupees or with both :

Provided that if any prisoner is found using the wireless communication device for attempting, abetting, conspiring or committing an offence inside or outside the jail premises and as a consequence there of an offence is committed, he/she shall on conviction be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three years and shall extend up to five years, or with fine which shall not be less than twenty thousand rupees and shall extend up to fifty thousand rupees or with both."

5. For section 43 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

Amendment of section 43

"43. Offences under section 42B to be cognizable and non-
Cognizable and bailable;
non-bailable
offence

" Offences under section 42B shall be cognizable and non-bailable."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Prisons Act, 1894 has been enacted to provide for the safe and secure custody of prisoners, their maintenance, admission and release, health, labour, punishment for jail offences to maintain jail discipline and duties of officers at various levels. Instances of usage of mobile phones and wireless devices by the prisoners and entering of persons by impersonation have been frequently noted. Therefore, it had been decided to amend the said Act in its application to the State of Uttar Pradesh to provide for stringent provisions for the possession and usage of mobile phones or other wireless devices and to provide adequate punishment for impersonator entering into Prison on the basis of false identity.

This Prisons (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 266, राजपत्र-2021-(598)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 82 सा० विधायी-2021-(599)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।